मुख्यमंत्री ने सुरेश रावत के पिता को श्रद्धांजलि दी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जल संसाधन मंत्री रावत के गांव मुहामी पहुंचे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अजमेर के मुहामी गांव जाकर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के पिता सूरज सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिनका हाल ही में निधन हो गया।

अजमेर/जयपुर, 30 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अजमेर के मुहामी गांव जाकर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के पिता सूरज सिंह रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्व. सूरज सिंह रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने सुरेश सिंह रावत एवं समस्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढ ढ स बंधाया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

- स्व. सूरज सिंह रावत को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण ओम प्रकाश भडाना भी थे।

लालबाग चा राजा के दर्शन किए शाह ने

मुंबई, 30 अगस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मुंबई के प्रसिद्ध गणेश मंडलों में से एक, लालबागचा राजा के दर्शन कर पूजा अर्चना की।

शाह के साथ उनकी पत्नी सोनल शाह, बेटे आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य लोग मौजूद थे। शाह गणेशोत्सव के अवसर पर दो दिवसीय दौरे पर मुंबई में हैं।

वह लालबागचा राजा के दर्शन करने से पहले फडणवीस के आवास "वर्षा" पर भी गए और भगवान गणेश के दर्शन किए तथा पूजा-अर्चना की।

- लालबाग चा राजा मुम्बई के प्रसिद्ध गणेश पंडालों में से एक है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह गणेश उत्सव पर दो दिन के दौरे पर मुंबई में हैं।

शाह हर साल अपने परिवार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने आते हैं।

उन्होंने आज दोपहर दक्षिण मुंबई स्थित राज्य सरकार के सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री शिंदे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संयुक्त महासचिव अतुल लिमये, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और मुंबई भाजपा प्रमुख अमित साटम से भी बातचीत की।

शाह गणपति दर्शन के लिए राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार के आवास पर भी गए और बांद्रा में वह उपनगरीय मुंबई के अंधेरी इलाके में एक गणपति पंडाल में गए।

बिहार की सही की गई वोटर लिस्ट में 67,826 संदिग्ध "डुप्लीकेट" मतदाता पाए गए

रिपोर्टर्स कलैक्टिव ने 15 चुनाव क्षेत्रों की वोटर लिस्ट की जांच के बाद यह खुलासा किया

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अगस्त। भारत के चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) की "शुद्ध की गई" बिहार की मतदाता सूची पर हुई एक चौंकाने वाली जांच ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का खुलासा किया है। इससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

द रिपोर्टर्स कलैक्टिव ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि सिर्फ 15 विधानसभा क्षेत्रों में ही 67,826 संदिग्ध डुप्लीकेट वोटरों के मामले पाए गए हैं। इन सभी में लगभग एक जैसी जानकारी दर्ज है। यह खोज चुनाव आयोग के "साफ की गई की गई मतदाता सूची" के दावे पर सवाल खड़ा करती है।

- इस खुलासे से चुनाव आयोग के शुद्ध की गई वोटर लिस्ट के दावे और निष्पक्ष व स्वच्छ चुनाव करवाने की चुनाव आयोग की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
- जो 67,826 डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनमें से 34,392 डुप्लीकेट मतदाता ऐसे हैं जिनका ब्यौरा भी एक जैसा है।
- उदाहरणार्थ, त्रिवेणीगंज की 20 वर्षीय अंजलि का नाम एक ही बूथ पर दो बार रजिस्टर्ड है। उसके पास दो वोटर आई.डी. नम्बर हैं पर बाकी डिटेल समान हैं।
- लौकहा विधानसभा सीट के 19 साल के अंकित कुमार का नाम भी एक ही बूथ पर दो बार है। बिस्फी सीट की 26 साल की अंजुम शेख का नाम भी दो बार है, पर दो अलग-अलग बूथों पर।

गहराई से जांच करने पर पाया गया कि इनमें से 34,392 मामलों में ऐसे वोटर हैं जिनके विवरण पूरी तरह से मेल खाते हैं और हर एक के पास दो-दो वोटर आईडी हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया था कि सभी डुप्लीकेट नाम हटा दिए गए हैं, लेकिन यह निष्कर्ष उनके दावे को गलत साबित करता है। सीमित संख्या वाले विधानसभा क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में डुप्लिकेट वोटरों का बने रहना, मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया में संभावित व्यवस्थागत संबंधी खामियों की ओर इशारा करता है।

यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब बिहार चुनाव की तैयारी कर रहा है। डुप्लीकेट वोटरों की मौजूदगी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है और जनता का लोकतंत्र पर भरोसा कम कर सकती है। अब चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ गया है कि वह बताए कि यह गड़बड़ी कैसे हुई।

लेकिन आयोग ने बिहार में हुई "स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एस.आई.आर.)" की प्रक्रिया से जुड़े अपने रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। जब रिपोर्टर्स-कलैक्टिव ने जानकारी मांगी, तो जवाब में आयोग ने एक लिंक भेज दिया जो मौजूद ही नहीं है।

जांच में सामने आया कि इनमें से 34,392 मामलों में मतदाताओं के विवरण पूरी तरह मेल खाते हैं और उनके पास दो-दो वोटर आईडी हैं। जबकि चुनाव आयोग का दावा है कि ऐसे डुप्लिकेट हटा दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, चुनाव आयोग ने त्रिवेणीगंज विधानसभा की 20 वर्षीय "अंजलि कुमारी" को दो वोटर आईडी जारी कर दी हैं। दोनों पर पति का नाम, उम्र और पता समान है। हैरानी की बात है कि उन्हें एक ही बूथ पर दो बार वोट डालने का अधिकार मिल गया है।

यह गड़बड़ी चुनाव आयोग द्वारा जल्दबाजी में किए गए "स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एस.आई.आर.)" का नतीजा है।

एस.आई.आर. एक अभूतपूर्व प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग उसी रफ्तार और उसी तरीके से पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रहा है।

बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2 से 3 लाख वोटर हैं। आंकड़ों के हिसाब से केवल कुछ ही मामले ऐसे होने चाहिए जहां दो अलग-अलग व्यक्तियों का नाम, रिश्तेदार का नाम और उम्र लगभग समान हो। लेकिन इस जांच में हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों डुप्लीकेट मामले सामने आए हैं।

जब तक चुनाव आयोग इन्हें अंतिम मतदाता सूची से नहीं हटाता, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। दिल्ली मुख्यालय में और राज्य व जिला स्तर पर मौजूद आयोग के अधिकारियों को कंप्यूटर प्रोग्राम और ज़मीनी सत्यापन के ज़रिए ऐसे डुप्लीकेट वोटरों (जिन्हें उनकी भाषा में डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज़ कहा जाता है) की पहचान करनी होती है, और यह प्रक्रिया प्रारंभिक मतदाता सूची बनने से पहले पूरी की जाती है। यह चरण अब बीत चुका है और आयोग दावा कर चुका है कि उसने 7 लाख डुप्लीकेट वोटरों को हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब इस मामले में और कोई सफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है।

लौकहा विधानसभा क्षेत्र में 19 वर्षीय अंकित कुमार का नाम दो बार दर्ज है। उनके पिता का नाम (अनिल महतो) और बूथ नंबर (371) दोनों बार समान हैं, लेकिन उनके पास दो वोटर आईडी नंबर हैं - ज़ैड.क्यू.क्यू. 3191681 और ज़ैड.क्यू.क्यू. 3217643

इसी तरह बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में 26 वर्षीय अंजुम शेख का नाम भी दो बार दर्ज है। एक जगह वह बूथ नंबर 91 पर वोटर के रूप में दर्ज हैं, ई.पी.आई.सी. ए.ए.वाय.3361391 के तहत, जहाँ उनके पिता का नाम मो. जावेद शेख लिखा है। वहीं दूसरी बार उनका नाम बूथ नंबर 89 पर दर्ज है, ई.पी.आई.सी. ए.ए.वाय. 3343621 के तहत, और यहाँ पिता का नाम मोहम्मद जावेद लिखा गया है।

मोदी ने जापान के प्र.मंत्री को कीमती पत्थर से बना बाउल सैट भेंट किया

टोक्यो/नयी दिल्ली, 30 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और उनकी पत्नी को शानदार उपहार भेंट किये जिनमें इशिबा के लिए कीमती पत्थर से बना बाउल का सेट और उनकी पत्नी के लिए पश्मीना शॉल शामिल है। चाँदी की चॉपस्टिक्स से सजे विंटेज कीमती पत्थर के बाउल भारतीय कलात्मकता और जापानी पाक कला की परंपरा का अनूठा मिश्रण है। चार छोटे बाउल और चाँदी की चॉपस्टिक्स के साथ भूरे रंग के मूनस्टोन से बने बड़े बाउल से सुसज्जित यह सेट जापान के डोनबुरी और सोबा अनुष्ठानों से प्रेरित है। आंध्र प्रदेश से प्राप्त यह मूनस्टोन बेहद चमकीला और प्रेम, संतुलन तथा सुरक्षा का प्रतीक है। बाउल का आधार मकराना संगमरमर है जिसमें राजस्थान की पारंपरिक शैली में अर्ध-कीमती पत्थर जड़े हैं।

मोदी ने ज़ेलेंस्की से फोन पर वार्ता की

पुतिन के द्विपक्षीय मुलाकात से पहले मोदी की वार्ता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है

नयी दिल्ली, 30 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों का पुरजोर समर्थन करता है।

चीन की दो दिन की यात्रा पर आज दोपहर तियांजिन पहुंचे मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। मोदी की चीन में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इस बैठक से पहले ज़ेलेंस्की के साथ मोदी की बातचीत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान के लिए शुरू से ही बातचीत तथा राजनयिक प्रयासों पर बल देता आया है। मोदी अपनी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है।

- प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ वार्ता में रूस-यूक्रेन संघर्ष, उसके मानवीय पहलू तथा शांति व स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचार हुआ।

प्रधानमंत्री ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने इस संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है।

मोदी ने कहा, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आज फ़ोन पर बात करने के लिए धन्यवाद। हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है।

'दुनिया का कोई भी देश भारतीय ड्रोन की टोह नहीं ले पाएगा'

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सबसे बड़े एयरो इंजन टैस्ट बेड का लोकार्पण करते हुए कहा

गौतमबुद्धनगर, 30 अगस्त। बदलती युद्ध रणनीतियों में ड्रोन के प्रयोग को जरूरी बताते हुये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे भारत के ड्रोन की अब अमेरिका और चीन समेत दुनिया का कोई भी देश टोह नहीं ले पायेगा।

सिंह ने गौतमबुद्धनगर में रेफी एम फाइबर प्रा. लि. द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एयरो इंजन टेस्ट बेड का लोकार्पण करने के अवसर पर कहा कि बदलती युद्ध रणनीतियों में ड्रोन का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन रक्षा नीति का अहम हिस्सा है और भारत अब इन्हें खुद डिजाइन और निर्माण कर रहा है। भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण से लेकर आज तक कभी भी दबावों के आगे हार नहीं मानी। आत्मनिर्भरता ही भारत की रक्षा और स्वाभिमान का आधार है। रेफी एम फाइबर जैसे स्टार्टअप इसका प्रमाण हैं कि हमारा नारा अब जमीन पर परिणाम दिखा रहा है।

- यह टैस्ट बैड रेफी एम फाइबर नामक स्टार्ट अप कंपनी ने बनाया है। सिंह ने कंपनी के संस्थापकों विशाल मिश्रा व विवेक मिश्रा की जोरदार सराहना की।

इस मौके पर उन्होंने संस्थान के संस्थापकों विशाल मिश्र और विवेक मिश्रा की उपलब्धि को भारत की नई तकनीकी क्रांति का प्रतीक बताया और कहा कि आज के युवा केवल एक कंपनी नहीं बना रहे, बल्कि रक्षा क्षेत्र में एक नई सोच और दिशा गढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6-6.5 वर्षों से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद उन्होंने इतनी कम उम्र के युवाओं को इतना बड़ा और इनोवेटिव एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करते नहीं देखा। अब जब भारतीय ड्रोन उड़ेंगे तो उन्हें न अमेरिका और न चीन, कोई डिटेक्ट नहीं कर पायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कमजोर करते हैं। जैसे ही सामान महंगे हो जाते हैं, उपभोक्ता उन्हें कम खरीदते हैं। इससे अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं की बिक्री घटती है, जो आयात पर बहुत निर्भर हैं और उन्हें ऑर्डर में कटौती करनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप, हर्ड कमजोर खपत समग्र मांग को घटाती है। राजन का कहना है कि जो अमेरिका प्रोटैक्शन में जो फायदा प्राप्त करता है, वह मांग में कमी के रूप में खो देता है, और यह व्यापार का एक ऐसा समझौता है, जो अंततः खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।

तीसरा, टैरिफ विकास को भी धीमा करते हैं। ये लगभग हमेशा बदले की कार्यवाही को प्रेरित करते हैं, और उदाहरण के तौर पर, भारत अमेरिकी कृषि निर्यातों जैसे कि बादाम, सेब या दालों पर उच्च शुल्क लगा सकता है। इससे पहले से ही कम मुनाफे वाले अमेरिकी किसान प्रभावित होंगे। साथ ही, आपूर्ति श्रृंखलाएँ रातों-रात समायोजित नहीं होतीं। यदि भारत से आयात महंगे हो जाते हैं, तो वियतनाम या मैक्सिको में आयात होने में समय लगता है। लॉजिस्टिक देरी होती है और लागत बढ़ जाती है। यह अनिश्चितता निवेश को हतोत्साहित करती है, जबकि कम निर्यात और धीमी उत्पादकता वृद्धि दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करती है।

इसी संदर्भ में, राजन टैरिफ़ को "सैल्फ गोल" बताते हैं। फुटबॉल में, सैल्फ गोल तब होता है जब एक खिलाड़ी गलती से अपनी ही टीम के खिलाफ गोल करता है। राजन का संकेत है कि ट्रम्प के टैरिफ़ राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यापार भागीदारों पर कठोरता का संकेत देते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये उल्टा असर डालते हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं, किसानों और व्यवसायों को होने वाला नुकसान टारगेट किए गए देशों को होने वाले नुकसान से अधिक होता है। प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के बजाय, ये अमेरिकी जनता पर कर लगा देते हैं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्थिर करते हैं।

राजन और कई मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों के लिए, टैरिफ़ भोथरे हो चुके और पुराने औजार हैं। ये शॉर्ट टर्म राजनीति में प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करते हैं क्योंकि ये दक्षता और नवाचार को हतोत्साहित करते हैं। उनका बड़ा संदेश यह है कि अमेरिका को टैरिफ़ दीवारों के पीछे छिपने के बजाय, घरेलू क्षमताओं-कौशल, बुनियादी ढांचा, अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए।

'राष्ट्रपति ट्रंप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फैसला अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से आएगा।

यह निर्णय उन टैरिफ्स पर केंद्रित है जो ट्रम्प ने अप्रैल में अमेरिका के लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर लगाए थे, साथ ही इससे पहले चीन, मैक्सिको और कैनडा पर लगाए गए शुल्क भी इसके दायरे में आते हैं।

ट्रम्प ने 2 अप्रैल को, जिसे उन्होंने "मुक्ति दिवस" कहा, उन सभी देशों पर 50 प्रतिशत तक के "पारस्परिक टैरिफ" लगाए, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटे में अर्थात आयात अधिक व निर्यात कम है। और अन्य लगभग सभी देशों पर 10 प्रतिशत का बुनियादी टैरिफ लगाया।

'भारत विश्व के गैर कानूनी घुसपैठियों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ बताया।

इस पर न्यायमूर्ति बागची ने याद दिलाया, राष्ट्रीय सुरक्षा तो ज़रूरी है ही। लेकिन हमारे पास एक साझा सांस्कृतिक विरासत भी है। कृपया इस पर भी सरकार की स्थिति स्पष्ट करें।

भूषण ने गृह मंत्रालय के उस सर्कुलर का हवाला दिया, और कहा जिसमें किसी व्यक्ति को देश से निष्कासित करने से पहले राज्य सरकार द्वारा जांच की बात कही गई है। इस मामले में कोई जांच नहीं हुई, फिर भी महिला को बाहर कर दिया गया गया।"

एक काल्पनिक स्थिति पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने पूछा, मान लीजिए, कि किसी व्यक्ति पर संदेह है और पुलिस फॉरेन्स एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज करती है। क्या ऐसे में व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जा सकता?

भूषण ने स्वीकार किया कि एफ आई आर की स्थिति में हिरासत संभव है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि हजारों लोग सिर्फ बंगाली बोलने की वजह से हिरासत में लिए जा रहे हैं।

एक बिंदु पर भूषण ने सॉलिसिटर जनरल की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, और कहा मिस्टर सॉलिसिटर, आपकी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियाँ यहां काम नहीं आएंगी।

अंत में, पीठ ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि कोलकाता हाई कोर्ट में लंबित हैबियस कॉर्पस याचिका जो सोनाली बीबी की नागरिकता से जुड़ी है, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी।

मेहता ने इस मामले को रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी याचिकाओं के साथ जोड़े जाने का सुझाव दिया और कहा कि यह घुसपैठ की बड़ी समस्या का हिस्सा है। लेकिन पीठ ने अलग से जवाब देने पर जोर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, आपने संबंधित याचिका में पहले ही जवाब दाखिल किया है। इस याचिका में भी जवाब दाखिल करें। यह एक बहुत जटिल मुद्दा है। कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर में तय की।

'प्रतिबंध के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बजाए कार्य व्यवस्था के नाम पर दूरस्थ स्थान पर कार्य करने में असमर्थ है। ऐसे में विभाग के आदेश को रद्द किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए अधिकरण ने याचिकाकर्ता का तबादला करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

नोबेल के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने मोदी को बताया था कि पाकिस्तान उन्हें नोबल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने जा रहा है। ट्रंप ने टेलीफोन पर मोदी से आगे कहा था कि भारत को भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, लेकिन मोदी ने ऐसा करने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डॉनल्ड ट्रंप की इन बातों से भारतीय नेता भड़क गये। उन्होंने टेलीफोन पर ट्रंप से कहा कि हालिया युद्धविराम में डॉनल्ड ट्रंप और अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। युद्धविराम भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर तय किया गया था। इसी के बाद से दोनों नेताओं के बीच के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गये। इसके बाद ही भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड वार्ता बेपटरी हो गई और अंत में अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि उसने ये खुलासा वॉशिंगटन और नई दिल्ली में 12 से ज्यादा अधिकारियों से की गई बातचीत के आधार पर किया है।

इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा है कि ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मोदी को वाइट हाउस आने का न्योता दिया था। दरअसल ये एक बड़े प्लान का हिस्सा था, क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर भी वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे।

ट्रंप ने मोदी को वाइट हाउस आमंत्रित किया था और वो चाहते थे कि वाइट हाउस में मोदी और असीम मुनीर के हाथ मिलाने का कार्यक्रम रखा जाए और इंटरनेशनल मीडिया में इसे अमेरिका की जीत की तरह प्रचारित किया जाए।

संसद में स्थापित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने के हमारे प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।"

पाधी ने कहा कि नंदीघोष (भगवान जगन्नाथ), दर्पदलन (देवी सुभद्रा) और भगवान बलभद्र (तालध्वज) के रथों के पहिए दिल्ली ले जाकर ओडिशा की कालातीत संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के स्थायी प्रतीक के रूप में स्थापित किए जाएंगे।

वार्षिक रथ यात्रा के बाद, देवताओं के तीनों रथों को हर साल खंडित कर दिया जाता है। नंदीघोष रथ के मुख्य बढ़ई विजय महापात्र के अनुसार, कुछ प्रमुख भागों को छोड़कर, हर साल रथों के निर्माण में नयी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। खंडित रथ के हिस्सों को गोदाम में रखा जाता है, और उनमें से कुछ नीलाम कर दिए जाते हैं, जिनमें पहिये भी शामिल हैं।

"एस.आई. भर्ती" रद्द करने पर गहलोत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैरानी के बात है कि इन परीक्षाओं को पेपरलीक से संबंधी एफआईआर में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा का नाम था और आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 60 लाख रूपयों में पेपर बेचने की साजिश की थी। इसलिए गहलोत का यह बयान की उन्होंने परीक्षा पेपरलीक के आरोप के कारण रद्द की गई थी, पर हैरानी होती है क्योंकि जिस आरपीएससी सदस्य का पेपरलीक की साजिश में नाम उजागर हो रहा था, उस सदस्य पर कार्यवाही करने या हटाने के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया।

यह बयान इसलिए भी चौंकाता है कि अब हाईकोर्ट का फैसला भी कह रहा है कि बाबूलाल कटारा गहलोत सरकार द्वारा नियुक्त आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य से संपर्क में थे और उन्हें अनुचित तरीके से मैरिट लिस्ट में आये अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलवाने की साजिश में शामिल थे।

गहलोत ने अपने बयान में अपनी सरकार द्वारा 'चीटिंग' को रोकने के लिए उठाए कदमों का ढिंढोरा पीटा और कहा कि उन्हीं की सरकार ने 'स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप' (एसओजी) में "चीटिंग व पेपरलीक मामलों के लिए "चीटिंग सैल" का गठन करवाया था, "और इसी (एसओजी) की जांच में ही पेपरलीक के बारे में खुलासे हो रहे हैं और आरोपी पकड़े जा रहे हैं।" परन्तु सत्य यह है कि एस.आई. भर्ती परीक्षा- 2021 में हुई व्यापक पेपरलीक को लेकर 10 एफ.आई.आर.-2021 में ही दर्ज करली गई थी, पर यह मामला एसओजी को जांच के लिए नहीं भेजा गया था। गहलोत सरकार के दौरान ही व्यापक पेपरलीक को लेकर छात्रों और

- एस.आई.भर्ती-2021 को रद्द करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि, शिक्षक ग्रेड-2 और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 में पेपरलीक को लेकर दर्ज एफ.आई.आर. में, जिस आर.पी.एस.सी. सदस्य का नाम आया था, वह गहलोत सरकार द्वारा नियुक्त आर.पी.एस.सी. सदस्यों से भी पेपरलीक से नकल करके आये अभ्यर्थियों को अच्छे अंक दिलाने की साजिश में लिप्त था।

अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की गुहार करी थी, परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया और आरपीएससी द्वारा लिखित परीक्षा रिजल्ट 24 दिसम्बर 2021 को जारी कर दिया गया, और फिर शारीरिक परीक्षा का रिज़ल्ट 11 अप्रैल 2022 को जारी कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि एसओजी ने इस मामले में 2 एफआईआर जनवरी 2024 और मार्च 2024 में दर्ज की थी, यानि वर्तमान सरकार में ही इस मामले की जांच एसओजी में पहुंची थी और जैसा गहलोत कह रहे हैं, उसके विरूद्ध, इस मामले की जांच वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नहीं। वर्तमान सरकार के दौरान ही एसओजी द्वारा की गई जांच के पश्चात ही 13 अगस्त 2024 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वी.के. सिंह, ने रिपोर्ट जारी की थी कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 की परीक्षा प्रक्रिया में गोपनीयता और पारदर्शिता भंग की गई थी जिस वजह से परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। उनकी जांच से यह भी सामने आया था कि परीक्षा से एक महीने पहले ही पेपरलीक हो गया था, इसका विस्तार बहुत अधिक है, यह जान पाना मुश्किल है कि कौनसा अभ्यर्थी चीटिंग करके चयनित हुए हैं और कौन नहीं।

यह भी उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि आरपीएससी सदस्यों को परीक्षा प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में अच्छे से जानकारी थी, इसलिए इतने व्यापक स्तर पर अंजाम दिया जा सका। अदालत ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कई परीक्षा केन्द्रों पर बायोमैट्रिक सिस्टम नहीं थे, जो डमी कैंडिडेट को परीक्षा में भाग लेने से रोकने में अहम् भूमिका निभाते हैं। कई केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, कई प्राइवेट स्कूलों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया जहां से पेपरलीक किया जा सकता था, और पूर्व में हुआ भी था। इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा अधिकारी नहीं थे और सुरक्षा अधिकारियों को अपनी पोस्टिंग के बारे में परीक्षा कार्यक्रम से बहुत पहले ही जानकारी दे दी गई थी, जिससे परीक्षा की गोपनीयता भंग हो गई। अदालत ने कहा कि आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं थी कि किस अभ्यर्थी को अंक दिये जा रहे थे और कैसे परीक्षा केन्द्र चयनित किये जा रहे थे।

गहलोत ने अपने बयान में इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी अगर आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की प्रक्रिया में त्रुटियां स्पष्ट थीं तो उनकी सरकार ने उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए थे।

"राष्ट्रदूत (एचएएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डोनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600